डी. स्टीफन जोसेफ

बनाम

भारत संघ और अन्य

अप्रैल 25,1997

[जी. एन. रे और जी. बी. पटनायक, न्यायमूर्ति]

सेवा कानूनः

पदोन्नति-सहायक अभियंता के पद के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण कनिष्ठ अभियंता के ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले व्यक्ति-तारीख से तीन साल की गणना की जाएगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रिब्यूनल में डिग्री प्राप्त करने का अभिनिर्धारित करना कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिग्री प्राप्त करने की तारीख से तीन साल की गणना अमान्य है-अपील किए जाने पर, किसी भी पिछले अभ्यास को नियम के रूप में विचार में नहीं लिया जा सकता है जिसका लंबे समय तक लगातार पालन किया जाता है। नियम तैयार करना-इसलिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

एम. बी. जोशी और अन्य। बनाम सतीश कुमार पांडे और अन्य। , [1993] सप्लीमेंट। 2 एस. सी. सी. 419, विश्वसनीय।

एन. सुरेश नाथन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। , [1992] पूरक। 1 एससीसी 484, विशिष्ट।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3118/1997

केंद्रीय विज्ञापन के 4.6.93 दिनांकित निर्णय और आदेश से 1993 के ओ. ए. सं. 577 में मंत्रालयी न्यायाधिकरण, मद्रास।

अपीलार्थी के लिए आर. वेंकटरमानी और एस. एम. गर्ग।

उत्तरदाताओं के लिए के. एन. शुक्ला, अवतार सिंह रावत, डी. एस. मेहरा, चंदन राममुर थी और वी. जी. प्रगसम।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

अनुमति दे दी गई।

पक्षकारों की विद्वान सलाह सुनी। छोटा सवाल जो उठता है कि इस मामले में निर्णय के लिए सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए है या नहीं डी. एस. जोसेफ बनाम भारत संघ जूनियर इंजीनियरों के ग्रेड में सेवा की गणना की जानी है यदि पदधारी 50 प्रतिशत कोटे में पदोन्नति के समय उनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी होती है।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मद्रास पीठ पदच्युत आदेश में कहा गया है कि जो उत्तरदाता कनिष्ठ अभियंता के पद पर हैं और उस श्रेणी में तीन साल की नियमित सेवा रखते हैं और जिनके पास विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री भी है, वे इस तरह के पद प्राप्त करने के हकदार होंगे। 50 प्रतिशत आरक्षित कोटे में पदोन्नति और उनके तीन साल के अनुभव को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने की तारीख से नहीं माना जाना चाहिए। इस मामले में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने इस तरह के फैसले पर आपत्ति जताई जा रही है।

अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री वेंकटरमानी ने तर्क दिया है कि सभी मामलों में नियम की सरल भाषा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है और इलेक्ट्रिकल

इंजीनियरिंग में डिग्री वाले जूनियर इंजीनियरों में से 50 प्रतिशत आरक्षण के लिए पदोन्नति के नियम को लागू करने में, पिछले अभ्यास पर विचार करने की आवश्यकता है जैसा कि इस न्यायालय ने एन. सुरेश नाथन और ए. एन. आर. बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में किया था। , [1992] पूरक। 1 एस. सी. सी. पृष्ठ 484। यदि उक्त नियम की व्याख्या करने के उद्देश्य से पिछले अभ्यास को ध्यान में रखा जाता है, तो यह स्पष्ट होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने की तारीख से हमेशा तीन साल के अनुभव की गणना की जाती थी। इसलिए, न्यायाधिकरण के निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत कोटे में निजी उत्तरदाताओं की पदोन्नति उक्त निजी उत्तरदाताओं को नहीं दी जा सकती थी।

हमें ऐसा लगता है कि राज्य सरकार गलत धारणा के तहत काम कर रही है कि पिछली प्रथा की प्रयोज्यता जैसा कि संकेत दिया गया है। सुरेश नाथन के मामले में, इस न्यायालय ने उक्त निर्णय में केवल यह संकेत दिया है कि पिछली प्रथा को बाधित नहीं किया जाना चाहिए बशर्ते कि इस तरह की प्रथा पदोन्नति के नियम के अनुरूप हो और कुछ समय पहले तक लगातार नियम को एक विशेष तरीके से लागू किया गया हो। हमारे विचार में, निर्णय नाथन का मामला केवल यह इंगित करता है कि पिछले अभ्यास को एक विशेष तरीके से व्याख्या करके नियम की प्रयोज्यता के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए। कुछ समय के लिए धीरे से। किसी भी पिछले अभ्यास से नियम को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि पिछले अभ्यास का लंबे समय तक लगातार पालन किया जाता है। नियम की व्याख्या करना। यहाँ यह संकेत दिया जा सकता है कि इसी तरह का एक प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष एम. बी. जोशी और अन्य मामलों में भी विचार के लिए आया था। सतीश कुमार पांडे और अन्य, [1993] पूरक। 2 एस. सी. सी. 419 बनाम सुरेश नाथन के मामले में निर्णय ने उस मामले के तथ्यों में अंतर किया

और यह संकेत दिया गया कि जब नियम की भाषा काफी विशिष्ट है कि यदि शैक्षणिक योग्यता के साथ फीडर पद पर सेवा की अवधि एक उम्मीदवार को पदोन्नति के लिए विचार करने में सक्षम करें, यह उचित नहीं होगा केवल वरिष्ठ के अधिग्रहण की तारीख से अनुभव को गिनना शैक्षिक योग्यता क्योंकि इस तरह की व्याख्या बहुत का उल्लंघन करेगी कर्मचारी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव।

तत्काल मामले में, कोई विवाद नहीं है कि पदोन्नति के लिए नियम 50 % कोटा 1982 और 1987 में लागू हुआ और उसके बाद केवल कुछ तदर्थ पदोन्नति दी गई। इसलिए आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं है। इस आधार पर कि पदोन्नति के लिए नियम 1982 से प्रभावी है नियम की व्याख्या देकर अलग तरीके से पालन किया गया जैसा कि था सुरेश नाथन के मामले में निर्णय में उल्लेख किया गया। इसलिए, हमारे विचार में, सुरेश नाथन के मामले में निर्णय, जो स्वीकृत के लिए एक अपवाद है साधारण भाषा पर नियम की व्याख्या का सिद्धांत, केवल इसके तहत विशेष परिस्थितियों में, मामले के तथ्यों में लागू होने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए, हम न्यायाधिकरण अंतिम निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। इसलिए यह अपील विफल हो जाती है और बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती है।

अपील को खारिज किया जाता है।

उपेन्द्र नारायण सिंह